Hkkjrh; turk ikVhZ
jk"Vªh; dk;Zdkfj.kh cSBd
दिनांक 29–30 मई 2006
नई दिल्ली

jktuhfrd izLrko

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपने गठन के दो वर्ष पूरे किए। यह वर्षगांठ जम्मू एवं कश्मीर में रक्तपात, शेयर बाजार में वज्राघात और सरकार द्वारा पैदा किए गए पूरे देश में चल रहे सामाजिक संघर्ष के बीच मनायी गई। यह घटनाएं अपवाद स्वरूप नहीं थी बल्कि उस भयंकर नुकसान की ओर इशारा करने वाली थी जिसे एक मौकापरस्त और टुकड़ों में बंटे एक गठबंधन ने इसे देश और देश की राजनीति पर थोपा है। यूपीए अपने एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर सत्ता में बने रहने की दावेदारी कर रहा है। लेकिन इसे एकजुट बनाये रखने में कोई आर्थिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि यूपीए के कुछ घटक दलों तथा वामपंथियों द्वारा मूल्यों, नीतियों एवं सुशासन का अवमूल्यन करने तथा भाजपा और उसके सहयोगी दलों को सरकार में नहीं आने देने की भावना से अधिक उत्प्रेरित है। इस गठबंधन का मूल उद्देश्य ही नकारात्मक है।

यूपीए सरकार से सबसे बड़ा नुकसान सुशासन को हुआ है। इसकी बड़ी पहचान संस्थाओं के प्रति इसका असम्मान भरा रवैया है। प्रधानमंत्री का पद भारत का राजनीतिक शक्ति का केन्द्रबिन्दु माना जाता है। जबकि यूपीए ने एक ऐसा तरीका ईजाद किया है जिसमें प्रधानमंत्री को अधिकारों से वंचित रखा जा सकता है। उन्हें अपनी कैबिनेट चुनने की आजादी नहीं है। उन्हें अपनी सरकार की नीतियां चलाने की आजादी नहीं है। वे अब राष्ट्रीय सलाहकार समिति जैसे गैर–जवाबदेह संस्था के अध्यक्ष के अधीन है। प्रधानमंत्री सत्तासीन तो है पर शक्तिहीन है। प्रधानमंत्री की न तो कोई धमक है और न ही साख़ और न ही उनसे कोई उम्मीद रखी जा सकती है। वे दया और सहानुभूति के पात्र है। आज से पहले कभी भी प्रधानमंत्री के पद को जानबूझ कर प्रभावशून्य नहीं बनाया गया।

वामपंथी दल कहने के लिए तो बाहर से समर्थन दे रहे हैं। फिर भी वे वीटो पावर रखते है जिसके द्वारा वे सरकार की वैचारिक दिशा निर्धारित कर रहे हैं। शासक दल और वामदलों के विरोधाभासी और द्वंद से भरे वैचारिक निर्देशों ने निर्णय–प्रक्रिया को पंगु बना दिया है। साहसिक निर्णय लेने का समय अब समाप्त हो चुका है। भारत जो बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ा था वह अब आम सहमति के अभाव में लड़खड़ा रहा है।

सहयोगी दलों ने इस सरकार की बंधक बना रखा है। वामपंथी वैचारिक एजेण्डा लागू करवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बिहार विधानसभा भंग करवाने में सफल रहे। सरकार के कुछ सहयोगी दल महत्वपूर्ण विभाग लेकर अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं और वे प्रधानमंत्री के प्रति भी जवाबदेह नहीं हैं।

यूपीए को विश्व की एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। यूपीए के सत्ता में आने के एक वर्ष पूर्व देश ने सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 प्रतिशत की दर से भी वृद्धि देखी। कृषि का उत्पादन रिकार्ड ऊंचाइयों पर था। निर्माण एवं सेवा के क्षेत्र आठ प्रतिशत से अधिक विकास दर बनाये हुए थे। सरकार के सामने सिर्फ चुनौती थी तो बस साहसिक निर्णय लेने की जिससे

उत्पादकता, कार्यकुशलता और अधिक आर्थिक गतिविधियां बढ़ें। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और वामदलों के वैचारिक मतभेदों ने आर्थिक क्षेत्र की निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। नेतृत्व को निर्णय लेना ही पड़ता है, वह आम सहमति की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। आज सभी जारी आर्थिक सुधारों पर विराम लग चुका है। पिछले दो सालों में अर्थव्यवस्था में जो भी वृद्धि हुई है वह पूरी तरह उद्यम के प्रभाव से है न कि नीतियों के प्रभाव से। दो हवाई अड्डों के निजीकरण के राजग सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को आगे बढ़ाने का काम छोड़ कर इस सरकार द्वारा एक भी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय नहीं लिया गया है।

आधारभूत संरचना के निर्माण के विषय में अर्थव्यवस्था एकदम ठहर सी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना में निविदाओं को देने में भ्रष्टाचार के चलते हो रही देरी के कारण यह परियोजना मंद गति से चल रही हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रारम्भ की गई ग्रामीण सड़क योजना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समुद्री पत्तनों का तेजी से विस्तार बंद हो गया है जिसके कारण वर्तमान व्यस्त पत्तनों से व्यापार काफी मंद गति से हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में क्षमता का विकास नहीं हुआ है और ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों को छोड़ दिया गया है। नदियों को जोड़ने की परियोजना का परित्याग कर दिया गया है। सीमेंट की कीमतें बढ़ी हैं और इससे निर्माण उद्योग की रफ्तार के धीमें होने का खतरा पैदा हो गया है। भाजपा यह मांग करती है कि मूल्य वृद्धि मापने का सूचकांक फिर से बनाया जाना चाहिए जिसमे जमीनी हकीकत प्रदर्शित हो।

मूलभूत चीजों की कीमतों में वृद्धि से भारत के लोगों का कष्ट और बढ़ा है। जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, सरकार ने अपना ध्यान अधिक टैक्स उगाही पर लगाया है जिससे तेल कम्पनियों को खतरा पैदा हो गया। आम आदमी पर तेल की कीमतों की वृद्धि का पूरा बोझ डाला जा रहा है। सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर आयात शुल्क घटाने में असमर्थ रही है जिससे आम आदमी को राहत मिल सके जो पहले ही दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ी कीमतों के बोझ तले कराह रहा है। यूपीए सरकार ने पिछले दो वर्षों में टैक्स का बोझ भी बढ़ाया है। खुदरा बाजार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति देना खतरे से खाली नहीं है और भाजपा इसका विरोध करती है।

पिछले दो वर्षों से करों में वृद्धि का सिलसिला पुनः प्रारम्भ हुआ है जो वर्ष 1991 से लगातार तर्कसंगत बनाया जा रहा था। लोगों पर बेतुके कर लगाये जा रहे हैं और राहत के क्षेत्र कम हो रहे हैं। भारत के पूंजी बाजार का आत्मविश्वास घटा है और हर स्तर के निवेशक चिंतित हैं।

आज भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में है। कई वर्षों के बाद पहली बार भारत को गेहूं आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और वह भी देश के किसानों को दी जाने वाली कीमत से कहीं अधिक कीमत पर। यूपीए द्वारा आर्थिक क्षेत्र में की गई छल–कपट की नीतियों से भारत के किसानों को सबसे अधिक चोट पहुंची है। किसानों की आत्महत्यायें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अलाभकारी साबित हो रहे हैं और अच्छे मानसून की भी संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। कृषि आय बीमा योजना को, जिसमें किसान काफी सुरक्षित महसूस करते थे, भुला दिया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में यूपीए की नाकामी बुरी तरह उजागर हो चुकी है और आम जनता को अनिर्णय और गैर जिम्मेदारी से भरी यूपीए को सत्ता में बनाये रखने की भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है।

यूपीए सरकार ने पिछले दो वर्षों में भ्रष्टाचार को एक संस्था का दर्जा दे दिया है। यूपीए मंत्रिपरिषद का अपराधीकरण करने में सफल रही है। इससे पहले कभी भी मंत्रिपरिषद के इतने

अधिक सदस्यों पर गम्भीर अपराधों के आरोप लगे नहीं थे। उन्हें एक शक्तिहीन प्रधानमंत्री में दाग को बचाने वाला व्यक्ति मिल गया। उन्होंने खुलेआम सार्वजनिक जीवन में शुचिता के सभी मानदण्डों को दरकिनार करते हुए घोषित किया कि मंत्रियों को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक वे दोषी न साबित हो। इन दागी मंत्रियों के कारण निर्लज्जता के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों को यूपीए सरकार ने खारिज कर दिया। वोलकर मामले के उद्घाटित तथ्यों से साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने राजनीति को व्यापार में बदल दिया। श्री नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी दोनों ईराकी तेल कूपनों के लाभार्थी थे जिन्हें लाभ के लिए बेचा जा सकता था। प्रधानमंत्री, श्री नटवर सिंह को 'क्लीन चिट' देने वाले पहले व्यक्ति थे। अब तो वे दागियों को 'क्लीन चिट' देने में काफी अनुभवी हो चुके हैं।

वोल्कर द्वारा मीडिया में हुए खुलासों से स्पष्ट पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी हमारे समय की सबसे भ्रष्ट संस्कृति की वाहक है। यूपीए सरकार ने सीबीआई का दुरूपयोग करते हुए कैप्टन सतीश शर्मा, शिबु सोरेन और बोफोर्स से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को दबा दिया। यूपीए सरकार ने तो यहां तक धृष्टता की कि ब्रिटिश बैंक में जब्त और फ्रीज किए गए क्वात्रोची के खातों को 'डी फ्रीज' करने के लिए क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को पत्र लिखने के लिए सीबीआई पर दबाव डाला। क्वात्रोची गांधी परिवार के करीबी मित्र हैं। स्कोंपीन सौदे से भी भ्रष्टाचार की बू आती है। सत्ता के करीबी लोगों के नाम मीडिया में उजागर हुए है और इसके प्रमाण भी हैं। पंजाब जैसे कांग्रेस शासित प्रदेशों में जमीन और शराब कांग्रेस पार्टी द्वारा राजस्व उगाही के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं।

संस्थाओं को बरबाद करने में यूपीए सरकार कांग्रेसी परम्परा की सच्ची अनुगामी रही है। पिछली सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को बदला गया और कई राज्यपालों को सिर्फ दलीय कारणों से हटाया और नियुक्त किया गया। इससे गवर्नर पद का राजनीतिकरण होना अवश्यम्भावी था। झारखण्ड, बिहार और गोवा जैसे कई राज्यों में राज्यपाल संविधान को तोड़ने मरोड़ने में कांग्रेस पार्टी के राजनैतिक उपकरण बन गए। बिहार विधानसभा को असंवैधानिक तरीके से भंग करने की भर्त्सना सुप्रीम कोर्ट ने भी की। निश्चित रूप से नितीश कुमार के नेतृत्व में राजग सरकार को सत्ता मे न आने देने के उद्देश्य से ही विधानसभा भंग की गई थी। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता यूपीए एवं वाम दलों के लिए परेशानी का सबब रही है। बिहार और पश्चिम बंगाल में यूपीए ने उसी चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर हमला किया जिसकी आम जनता ने काफी प्रशंसा की थी। यूपीए ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को समाप्त करने की रणनीति बनायी है।

श्री नवीन चावला जैसे एक दल के प्रति निष्ठा रखने वाले नौकरशाह को चुनाव आयोग का सदस्य बनाया गया। उनकी दलीय गतिविधियों में अपने राजनीतिक न्यास संस्था के लिए कांग्रेस के सांसदों से सांसद निधि से अनुदान लेना शामिल हैं। करीब 205 सांसदों ने राष्ट्रपति के पास पहुंच कर मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा श्री नवीन चावला को हटाने की गुहार की। प्रधानमंत्री ने इस संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित करते हुए इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी राय देने से रोक दिया।

संविधान की दुर्गति करने की बात कांग्रेस पार्टी के लिए नई नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 102 का प्रमुख उद्देश्य सांसदों की स्वतंत्रता को कायम रखना था ताकि सरकार उनके प्रति जवाबदेह रहे। विधायिका के सदस्यों को सरकार से लाभ नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार के हितों के विरोधाभास से उनकी स्वतंत्रता पर आंच आती है। यूपीए ने इस प्रमुख संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने का निर्णय लिया। अब यूपीए सरकार ने इस असंवैधानिकता को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए कानून बना दिया है और उन लोगों का बचाव किया है, जिन्होंने संविधान का

उल्लंघन किया। लगभग 40 सांसदों को अयोग्यता से बचाने की कोशिश की गई है जबकि लाभ के पद पर रहने के कारण उनकी सीटों को रिक्त घोषित किया जाना चाहिए था। हाल ही में सत्तासीन गठबंधन ने स्पीकर के निर्णय की आलोचना करने के कारण एक गणमान्य नागरिक की जिस तरह भर्त्सना करने का उदाहरण रखा है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिए खतरा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय ने यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता और रवैये पर गम्भीर शंका खड़ी कर दी है। वोट बैंक की राजनीति की फिराक में सरकार ने जानबूझ कर आतंकवादियों के प्रति नरम बने रहना पसंद किया है। सरकार के कार्यकलापों से मिलने वाले संकेत बार–बार लोगों को यही दर्शा रहे हैं कि आतंकवाद के साथ नर्मी बरत कर नहीं लड़ा जा सकता है। आतंकवाद–विरोधी कानून 'पोटा' का आधार वैश्विक–मॉडल के अनुरूप तैयार किया गया था, जिसे ऐसे सभी अत्यंत उदारवादी लोकतांत्रिक देशों ने अपनाया था, जिन पर आतंकवाद का साया छाया है। यूपीए सरकार ने आतंकवादियों के प्रति नर्म रूख अपना कर इस कानून को निरस्त कर दिया, जिसमें आसानी से जमानत मिलने का प्रावधान भी शामिल कर दिया गया है।

कश्मीर में यूपीए सरकार की नीति एकदम बेकार रही है। प्रधानमंत्री ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल का जश्न मनाते हुए श्रीनगर के सभी ग्रुपों को गोलमेज कांफ्रेंस में आमंत्रित कर लिया। कुछ कांग्रेस के हिमायती संगठनों को छोड़ कर सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इस कांफ्रेंस में भाग लेने से कोई लाभ नहीं होगा। भाजपा ने इसमें भाग इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें संदेह है कि सरकार आतंकवाद से लड़ना ही नहीं चाहती। 8 वर्ष बाद, फिर से जम्मू के डोडा जिले में आतंकवाद लौट आया है और वहां तेजी से हिन्दुओं का सफाया किया जा रहा है। इस जिले के हिन्दुओं को सुनियोजित ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से लोगों ने अपने प्राण गवां दिए और यह सरकार निष्क्रिय होकर, बिना किसी रणनीति और सोच के सब कुछ होते देख रही है। आतंकवादी कश्मीर घाटी में मनमर्जी से हमला कर रहे हैं। घाटी में कई ग्रुपों तथा जम्मू और लद्दाख के अनेक संगठनों ने संदेह प्रगट किया है कि सरकार की अब कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है कि वह कश्मीर की बातचीत को गम्भीरता से आगे बढ़ाना भी चाहती है।

पिछले दो वर्षों में माओवाद का तेजी से बढ़ता विस्तार अत्यंत खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। आज माओवादी गलियारा नेपाल से शुरू होकर भारत में महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक पहुंच गया है। कुछ राज्यों में माओवादी ग्रुपों ने विद्रोह की योजना बनाकर कई कस्बों को अस्थायी रूप से कब्जा करने का साहस तक कर लिया है। फिर भी 2004 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अनेक माओवादी ग्रुपों के साथ गुपचुप तरीके से राजनैतिक गठजोड़ किया था। इसके परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश में चुनावों के बाद उन्होंने माओवादी गतिविधियों पर नर्म रूख अपना लिया है। आज यह गम्भीर खतरे डा. मनमोहन सिंह के समक्ष खड़े है, परन्तु उनकी सरकार ने इससे निपटने के लिए कोई ठोस योजना तैयार नहीं की है।

राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते हुए यूपीए सरकार अल्पसंख्यकवाद की नीति का अनुसरण कर रही है। ऐसी बेतुकी नीति के चलते बांग्लादेश से भारत पर जनसांख्यिकीय हमले को हवा मिल रही है। घुसपैठ अनियंत्रित ढंग से चल रही है और इसका सबसे बुरा उदाहरण हमें असम में राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी पड़ती राजनीति के उदाहरण से मिल जाता है। पूरे विश्व में, यदि किसी विदेशी पर नागरिकता का प्रश्न खड़ा किया जाता है तो उस विदेशी को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होती है। विदेशी व्यक्ति पर प्रमाण सिद्ध करने का दायित्व रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर आईएमडीटी एक्ट को रद्द कर दिया था कि यह घुसपैठियों के अनुकूल बैठता है और इसके चलते 'बाहरी आक्रमण' जैसी स्थितियां बनी हैं। यूपीए सरकार ने तुरन्त ही एक आदेश जारी कर दिया जिसके कारण सरकारी अधिकरणों पर यह जिम्मेदारी स्थानांतरित हो गई कि वे यह साबित करे कि

वह विदेशी व्यक्ति भारतीय नहीं है। धर्म–आधारित आरक्षण संविधान की भावना के एक दम विपरीत है और फिर भी राज्यों में कांग्रेस सरकारें इसका खुला उल्लंघन करती जा रही हैं। अल्पसंख्यकवाद के ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है, जिनमें मजहब के आधार पर सेना में लोगों की गिनती तथा रेलवे मंत्रालय में जस्टिस बनर्जी समिति की स्थापना शामिल है ताकि उन अभियुक्तों की मदद हो सके जिन्होंने गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे को जलाया था। हमारे सशस्त्र सेना बल हमेशा इस प्रकार की विभाज्यता से अलग रहे हैं और उन्होंने अद्‌भुत अनुशासन कायम रखा है। यूपीए सरकार ने सेना में मजहब–आधारित जनगणना करा कर इन संस्थाओं में दरार पैदा करने की कोशिश की है। सरकार को जनमत के भारी दबाव के चलते इस निर्णय से पीछे हटना पड़ा। गोधरा मामले में न्यायालयों ने पहले ही अभियुक्तों को बार–बार जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया है और उनके खिलाफ ढेर सारे प्रमाण इकट्‌ठे हो गए हैं। फिर भी यूपीए सरकार ने कानून के खिलाफ रेल– जांच बिठाने का निर्णय लिया और उसने भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश की सलाह लिए बिना ही इस जांच के नेतृत्व के लिए जज चुन लिया। अपने मतलब की एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई ताकि अभियुक्तों को मदद मिले। इससे उन मजहबी कट्‌टरवादियों को संकेत पहुंचा है कि यूपीए सरकार उन्हीं के साथ खड़ी है, भले ही उन्होंने रेलगाड़ी जलाने जैसा घृणित अपराध ही क्यों न किया हो।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इसके मंत्री महोदय का काम–काज बेहद निराशाजनक है। एनडीए ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास किया परन्तु उसके बाद से भारत के इस नए क्षेत्र को विफल करने की कोशिश जारी रही। दो वर्षों तक कोई उपाय नहीं किए गए, यह इरादा भी नहीं जताया कि भारत में शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट बनाया जाए। मानव संसाधन मंत्रालय का एजेण्डा बड़े शर्मनाक ढंग से राजनैतिक बना हुआ है। अधिकारी– कर्मचारियों के चयन से लेकर पाठ्‌यक्रम बनाने तक की पूरी प्रक्रिया वोट–बैंक राजनीति से प्रेरित रहती है।

यूपीए सरकार ने जिस ढंग से आरक्षण पर अपना आचरण दिखाया है उससे सभी में यह शक पैदा हो रहा है कि इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय न होकर समाज में तनाव पैदा करना है। भारतीय जनता पार्टी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करने के लिए संविधान संशोधन का समर्थन किया था। किन्तु ऐसा करते हुए, विभाजकता से बचना जरूरी है। इस प्रकार की पहल के लिए आम सहमति बनाना जरूरी है। यूपीए सरकार इसमें असफल रही है। सबसे पहली बात सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षण का कार्यान्वयन करने के लिए योग्यता को दबाया न जाए और संस्थाओं की उत्कृष्टता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि आरक्षण का लाभ समाज के वंचित वर्ग में भी सबसे अधिक वंचित वर्ग तक पहुंचे। तीसरी बात सरकार यह सुनिश्चित करे कि अगड़ी जातियों के गरीब वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिले। विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जानी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि इन तीनों आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान दिया जाए। भाजपा अल्पसंख्यक संस्थाओं को आरक्षण लागू करने की बाध्यता से दूर रखने का विरोध करती है। साथ ही साम्प्रदायिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। भाजपा इस पर चिंता व्यक्त करती है कि राजग सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने की संभावनाएं ढूंढने के लिए बनाई गई समिति को केन्द्र सरकार ने भंग कर दिया है।

यूपीए ने अलग तेलंगाना राज्य के गठन के वायदे को भी दरकिनार किया है और लोगों में निरन्तर बेचैनी बढ़ रही है और वे ठगे से महसूस करते हैं। भाजपा ने एक अलग तेलंगाना राज्य बनाये जाने के बारे में जनता की तीव्र आकांक्षा का सदैव समर्थन किया है।

पिछले दो वर्षों में यूपीए सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रबंधन में हमारी नीतियों की स्वायत्तता का परित्याग स्पष्ट रूप से देखने में आया है। साथ ही इसमें अस्थिरता एवं विरोधाभासी खींचतान के साथ–साथ वैचारिक मतभेदों से भरे तथा टूटे–फूटे गठबंधन के दबावों का भी सामना करना पड़ा है। पिछले दो वर्षों में नीतियों की गलत समझ और कुप्रबंधन के चलते हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा है। यह दुख की बात है कि भारतीयों को अपने उद्यम एवं गतिशीलता के कारण जो पहचान मिली थी उसे भारतीय राजनय के प्रति सम्मान के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सका। निश्चित रूप से मुद्दों पर नासमझी और दूरदृष्टि के अभाव वाले रवैये के कारण राजग सरकार द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों को विसर्जित होने दिया गया है।

यूपीए सरकार ने सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के भीतर जनवरी 2004 के इस्लामाबाद घोषणा की कमजोर कर दिया जिसके चलते राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की वचनवद्ध बाध्यता छोड़ने का अवसर मिल गया। शान्तिवार्ता की प्रक्रिया से आतंकवाद को अलग कर देना एक गंभीर भूल है, जिसका खामियाजा भारत को अपने नागरिकों और सुरक्षा बलों की जिन्दगी देकर भुगतना पड़ेगा। मुद्दों पर नरम रवैया रखने के कारण ही बांग्लादेश इस्लामी आतंकवाद का नया केन्द्र बनकर उभरा है। बांग्लादेश की भारत के साथ खुली सीमाएं हैं जो आतंकवादियों के लिए आसान रास्ता साबित होती हैं और वहां उनकी शरणगाह है और वहां से लगातार आव्रजन की प्रक्रिया जारी है। यूपीए सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ आतंकवाद के मुद्दों पर ढिलाई बरती है। सरकार ने सियाचिन को सेनाविहीन करने पर बातचीत करने के खतरनाक संदेश दिए हैं। भाजपा जहां ऐसे किसी भी कदम का विरोध करती है जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो वहीं यूपीए से यह मांग भी करती है कि वह सियाचिन, अवैध आव्रजन और सीमा पार–आतंकवाद पर अपनी नीति की घोषणा करे।

भाजपा नेपाल में जारी माओवादी आन्दोलन से भारत की सुरक्षा को होने वाले खतरे को गम्भीरता से लेती है। यह खतरा यूपीए सरकार की स्पष्ट दिख रही लापरवाही के कारण और बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि भ्रम और जड़ता की शिकार यूपीए सरकार अपने पड़ोसी देश में हो रही गतिविधियां से एकदम निश्चिंत है। इससे भी बुरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी नेपाल नीति माकपा के हवाले कर दी है। भाजपा इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीतिगत बयान की मांग करती है।

अमरीका के सम्बन्ध में भी यूपीए सरकार ने भारत के सामरिक हितों को वार्ता की मेज पर रख दिया है। परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोगों से सम्बन्धित समझौते को इस सीमा तक खींचा गया कि हमारी न्यूनतम परमाणु निवारक क्षमता का भविष्य अब खतरे में पड़ गया है। भाजपा का इस नीति की जनक के रूप में यह मानना है कि भारत और अमरीका के बीच बहुत स्वस्थ सम्बन्ध होने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध साझा संघर्ष में साथ देना चाहिए लेकिन यह सब बराबरी के स्तर पर होना चाहिए। भारत के अपने सामरिक हितों जिसमें ऊर्जा के हित शामिल हैं को अमरीकी सामरिक निर्देशों और आदेशों के आगे गिरवी नहीं रखा जा सकता।

अपने शासनकाल में एनडीए सरकार की विदेश नीति का एक मात्र आधार राष्ट्रीय हित रहा है। पिछले दो वर्षों में यूपीए सरकार ने दूसरी बातों पर विचारों को महत्त्व देना शुरू कर दिया, जिनमें वैचारिक भावना और वोट बैंक राजनीति के शामिल होने से यह निर्णय प्रभावित होने लगे। भाजपा निरन्तर यही प्रयास करेगी कि राष्ट्रीय हित ही एकमात्र हमारी विदेश नीति की कसौटी बना रहे।

———